MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand to restart UPSC Residential Coaching Centre at Haj House, Mumbai

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में खड़ा होकर हाशिए पर मौजूद देश के लाखों एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रहीं श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डा. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, MANUU, हैदराबाद, AMU, अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दूरदराज के गांवों से आने वाले बच्चों ने मंहगी यूपीएससी कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमियों में एडमिशन लेना शुरू किया और प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के उनके सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेज़ से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल तक शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट्स भी बढ़िया रहे। उसने कई आईएएस दिए, कई आईपीएस दिए और महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज़ में भी बच्चे सेलेक्ट होने लगे। इसके बाद कोविड आया। तब पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वे सैंकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए।

सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधान मंत्री जी को प्रोटोकॉल तोड़ कर कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूँ, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधान मंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि काश प्रधान मंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह से अपनेपन का एहसास दिला पाते। कभी जब मैं प्रधान मंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ कर रिसीव करते हुए देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कभी प्रधान मंत्री जी अपने देश की बेटी बिलकिस को भी इसी तरह से अपनेपन का एहसास दिला पाते। कभी कैफ़ भोपाली ने कहा था :

'ये दढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलतीं,
हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलतीं,
क़बीले वालों के दिल जोड़िए मिरे सरदार,
सरों को काट कर सरदारियाँ नहीं चलतीं।'

…(**व्यवधान**)…

सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। ...(**व्यवधान**)... इसको न सिर्फ शुरू किया जाए, बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएँ। ...(**व्यवधान**)... जब पैसा सरकार को नहीं देना है, बल्कि हाजियों का जो corpus सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इस कोचिंग सेंटर को चलना है, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज़ में इसे शुरू करने में सरकार को क्या परेशानी है?...(**समय की घंटी**)... सर, यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्री महोदय बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपया इसका संज्ञान लें, क्योंकि देश के लाखों छात्र आपसे गुजारिश कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Imran Pratapgarhi : Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri K.R.N. Rajeshkumar (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Now, Shrimati Sonia Gandhi; Concerns over the dilution of employment guarantee under MGNREGA.

Concerns over the dilution of employment guarantee under MGNREGA

SHRIMATI SONIA GANDHI (Rajasthan): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on a very important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance. The right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi NREGA, also known as MGNREGA, was enacted by the then UPA Government in 2005 under the leadership of Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP Government has systematically undermined the scheme. The Budget allocation remains stagnant at Rs.86,000 crore, a ten year low as percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective Budget has been declined by Rs.4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20 per cent of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar Based Payment System and the National Mobile Monitoring System,